>

Title : Need to give approval to the Bihar Sugarcane Amendment Bill, 1981.

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : बिहार की सरकार ने विकसित बिहार के निर्माण हेतु कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया है क्योंकि बिहार में खदान एवं उद्योगों की कमी है। राज्य सरकार ने 23 नई चीनी मिलों एवं एथनॉल के लिए मेगा प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है, जिसमें पांच बिलियन डालर का निवेश होगा एवं 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। गन्ने से सीधे-सीधे एथनॉल हासिल करने के लिए बिहार विधान मंडल ने बिहार सुगरकेन विधेयक 1981 में संशोधन को मंजूरी दे रखी है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अप्रैल, 2007 में ही भेजा गया पर यह लंबित है। स्वयं मा0 प्रधान मंत्री जी ने भी समय-समय पर पर्यावरण की दृष्टि से पेट्रोल एवं डीजल में एथनॉल मिश्रण की बात कही है। बिहार के संशोधन प्रस्ताव को मंजूर करने की जगह एक ऐसा आदेश भारत सरकार ने निकाल दिया है, जिसके तहत यह निर्देश है कि सिर्फ पुरानी चीनी मिलें ही गन्ने से एथनॉल का उत्पादन कर सकती है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र के इस आदेश को वापस लिया जाये एवं लंबित पड़े संशोधन विधेयक की मंजूरी प्रदान करायी जाये।